

ट्रंप का बड़ा बयान: भारत के साथ जल्द होगा 'बहुत बड़ा' व्यापार समझौता



वाशिंगटन, डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ऐलान किया कि अमेरिका ने चीन के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जल्द ही भारत के साथ एक बहुत बड़ा व्यापार समझौता होने की संभावना है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित 'बिंग ब्यूटीफुल इवेंट' में कहा, हमने कल चीन के साथ समझौता किया। हम हर किसी के साथ डील नहीं करने जा रहे, लेकिन हमारे पास कुछ शानदार समझौते हैं। भारत के साथ शायद एक बहुत बड़ा समझौता होने वाला है। हम भारत को खोलने जा रहे हैं। ट्रंप ने हालांकि चीन के साथ हुए समझौते का ब्योरा नहीं दिया, लेकिन व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि यह मई में जिनेवा में हुए समझौते पर आधारित है, जिसमें चीन ने दुर्लभ खनिजों और मैग्नेट जैसे महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति करने पर सहमति जताई है। भारत के साथ चल रही बातचीत ९ जुलाई की समय सीमा से पहले महत्वपूर्ण हो गई है, जब भारत २६ प्रतिशत तक पारस्परिक शुल्क लगाने की योजना बना रहा है। भारतीय व्यापार वार्ताकार वर्तमान में वाशिंगटन में हैं, और यह दौर पिछली वार्ताओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो कृषि और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर कम प्रगति के साथ समाप्त हुआ था। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि ९ जुलाई की समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह निर्णय राष्ट्रपति पर निर्भर है। हमारी टिप्पणी: ट्रंप का यह बयान भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो पहले से ही १०० बिलियन डॉलर से अधिक का है। यह समझौता, यदि सफल होता है, तो भारत के वैश्विक व्यापार प्रोफाइल को और मजबूत कर सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत को अपने किसानों और डिजिटल क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह समझौता जल्दबाजी में या एकरतफा न हो। यह देखना रोचक होगा कि क्या यह बड़ी डील दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगी, जैसा कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फरवरी २०२५ में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद संकेत दिया था। स्रोत: ईटीवी भारत, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड

१५०० सालके ‘जश्रे विलादत-ए-नबी’ के लिए जागरूकता बैठक

जमीर काज़ी मुंबई: माहे मुहर्रम की पहली तारीख के मौके पर नबी-ए-करीम सल्लल्लुम के की १५०० साल के जश्रे विलादत को शानदार और ऐतिहासिक अंदाज़ में मनाने के उद्देश्य से हां डीवाला मस्जिद, सिल्वर जुबली एस्टेट, मुंबई-३ में एक अहम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह बैठक जुम्मे की नमाज़ के बाद हुई, जिसकी सदारत धार्मिक व सामाजिक रहनुमा और रज़ा अकैडमी के सरबराह हाजी मुहम्मद सईद नूरी साहब ने की। इस मौके पर मशहूर आलिम-ए-दीन मौलाना एजाज़ अहमद कश्मीरी ने बहुत ही असरदार और ख़ास अंदाज़ में सीरत-ए-नबी, जश्रे विलादत के मकसद और उम्मत-ए-मुस्लिमा की इस्लाह पर रौशनी डाली। अपने तक्रीर में मौलाना कश्मीरी साहब ने कहा: १५०० वर्षीय जश्रे विलादत-ए-नबी ६ सिर्फ़ खुशी मनाने का मौका नहीं है, बल्कि यह एक अहम जिम्मेदारी है कि हम नबी-ए-अकरम ६ की तालीमात को आम करें और खुद भी उन पर अमल करें। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नमाज़ी, मकामी उलमा, नौज़वान और मुहतरम शहरी शामिल हुए। अवाम से अपील की गई कि वे इस तारीखी मौके को ईमान अफ़रोज़ तरीके से मनाएं और इतेहाद व भाईचारे का पैगाम आम करें। इज़्जताम पर हाजी मुहम्मद सईद नूरी साहब ने दुआओं के साथ कौम व मि़ल्लत की भलाई, फ़िलस्तीन व ग़ज़ज़ा के मज़लूमों और दुनिया भर के मुसलमानों के अम्म व सलामती के लिए दुआ की।

लोकनेता विनायक राव मेटे को सदाभाऊ खोत ने दी श्रद्धांजलि

बीड (प्रतिनिधि): महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कृषि राज्य मंत्री एवं रयत क्रांति संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आ. सदाभाऊ खोत ने बीड जिले के दौरे के दौरान शिवसंग्राम संगठन के संस्थापक अध्यक्ष लोकनेता विनायक राव मेटे के स्मृति स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सदाभाऊ खोत ने कहा कि बीड जिले में मेरे इस दौरे की शुरुआत मैंने सबसे पहले विनायक राव मेटे साहब को प्रणाम करके की। सदाभाऊ खोत ने भावुक होकर कहा कि जो भी व्यक्ति लोकनेता विनायक राव मेटे के संपर्क में आता था, वे उसे अपनापन देते थे। राजनीतिक मंच पर वे बेबाक राय रखते थे, लेकिन निजी संबंधों में वे गहरी दोस्ती निभाते थे। दोस्ती की दुनिया में उन्हें राजा जैसा माना जाता था। उन्होंने आगे कहा, जब हम सभी घटक दल एकजुट हुए थे, तो सबको एकजुट रखने का काम मेटे साहब ने ही किया। महायुति की सभी बैठकें उनके नेतृत्व और योजनाओं के तहत ही होती थीं। मराठा आरक्षण के मुद्दे को विधानमंडल में बेहद संजीदगी और जोश के साथ अगर किसी ने उठाया था तो वे मेटे साहब ही थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का अरब सागर में स्मारक बनना चाहिए – इस विचार को सबसे पहले मेटे साहब ने ही आगे बढ़ाया और उसके लिए संघर्ष भी किया। उनके जाने से जो स्थान खाली हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने शिवसंग्राम कार्यकर्ताओं को आश्वासन करते हुए कहा, शिवसंग्राम के कार्यकर्ता खुद को अकेला न समझें। मैं भी शिवसंग्राम परिवार का हिस्सा हूं और हमेशा संगठन के साथ मज़बूती से खड़ा रहूंगा। सदाभाऊ खोत ने यह श्रद्धांजलि गहरे भाव से दी और उनके शब्दों में मित्रता, सम्मान और प्रतिबद्धता की सच्ची झलक दिखाई दी।

महाराष्ट्र पुलिस विभाग में ५५ अधिकारियों का तबादला, अविनाश बारगळ को लातूर प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया

जमीर काज़ी। मुंबई, २७ जून २०२५ महाराष्ट्र राज्य पुलिस विभाग में अधीक्षक से अपर अधीक्षक दर्जे के कुल ५५ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए, जिसमें मुंबई पुलिस विभाग के १२ से अधिक अधिकारी भी शामिल हैं। बीड जिले में घटित संतोष देशमुख हत्याकांड के बाद हटाए गए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ को अब लातूर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया है। इस तबादला सूची में कुछ अधिकारियों को 'क्रीम पोस्टिंग' (अहम पदस्थापन) भी दी गई है, जबकि कई अधिकारी जो पिछले कुछ महीनों से पोस्टिंग से वंचित थे, उन्हें भी स्थान मिला है। करीब तीन वर्षों से 'एसआईडी' (राज्य खुफिया विभाग) में कार्यरत आईपीएस वसंत जाधव को अब मुंबई पुलिस दल में नियुक्त किया गया है। वहीं, राज्य सुरक्षा महामंडल में कार्यरत आईपीएस अश्विनी सानप को पुणे रेलवे पुलिस बल में भेजा गया है। पिछले महीने कोल्हापुर से ठाणे पुलिस में स्थानांतरित हुए महेंद्र पंडित को अब मुंबई पुलिस दल में नियुक्त किया गया है। अहमदनगर (अहिल्यानगर) के भरत तागडे को नाशिक एससीबी (विशेष शाखा) में गोंदिया के अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा को नागपुर शहर उपायुक्त पद पर अकोला के अपर पुलिस अधीक्षक अभय डॉंगरे को गोंदिया का नया अपर पुलिस अधीक्षक वहीं, चंद्रपुर आयआरबी-४ की समादेशक भाग्यश्री नवटके को गोंदिया आयआरबी-२ की समादेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी यह तबादला आदेश राज्य में आगामी कानून व्यवस्था, चुनावी व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर किया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उमाकिरण क्लासेस सील, कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात

आरोपी विजय पवार और खटावकर की तलाश में पुलिस खाना

बीड। संवाददाता शहर के चर्चित उमाकिरण क्लासेस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संस्था को सील कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान इलाके में कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया था। वहीं, इस मामले से जुड़े मुख्य आरोपी विजय पवार और खटावकर की तलाश में पुलिस टीम खाना कर दी गई हैं। शहर में इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि संस्थान से जुड़े कुछ गंभीर आरोपों के चलते यह कदम उठाया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक इस संबंध में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। उमाकिरण क्लासेस पर हुई यह कार्रवाई शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक जरूरी कदम मानी जा सकती है। यदि किसी शैक्षणिक संस्था पर आपराधिक गतिविधियों या अनियमितताओं के आरोप सिद्ध होते हैं, तो ऐसे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। यह न सिर्फ छात्रों के भविष्य की रक्षा करता है, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास भी बनाए रखता है।

दो दशकों बाद ठाकरे बंधु एकजुट!

हिंदी भाषा थोपने के विरोध में ५ जुलाई को मोर्चा

रिपोर्ट: रामिज काज़ी। मुंबई राज्य की राजनीति को नई दिशा देनेवाली बड़ी घटना शुक्रवार को सामने आई। पिछले कुछ हफ्तों से चल रही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के मिलन की चर्चा को नया मोड़ मिला है। पहली कक्षा से हिंदी भाषा लागू करने के सरकारी निर्णय के विरोध में आयोजित आंदोलन के तहत अब दोनों भाई एक मंच पर नजर आएंगे। मनसे द्वारा ५ जुलाई को निकाले जानेवाले मोर्चे में उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। इस बात की जानकारी शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता व संजय राऊत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि ठाकरे बंधु किसी पार्टी के झंडे तले नहीं बल्कि मराठी भाषा और अस्मिता के एजेंडे के साथ एकजुट हो रहे हैं। वहीं, मनसे नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि यह मोर्चा संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन २.० के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) समेत सभी नेताओं से अपील की कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मराठीप्रेमी आंदोलन में शामिल हों। इस मोर्चे में राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) की सहभागिता तय हो गई है, जबकि कांग्रेस ने भी सकारात्मक रुख अपनाया है। राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इस आंदोलन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा और इसका असर बृहन्मुंबई महानगरपालिका सहित आगामी स्थानीय निकाय चुनावों पर भी पड़ सकता है। उद्धव और राज ठाकरे ने गुरुवार को अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदी भाषा थोपे जाने के विरोध में मोर्चा निकालने की घोषणा की थी। राज ठाकरे की योजना ६ जुलाई को गिरगांव चौपाटी से मोर्चा निकालने की थी जबकि उद्धव ठाकरे ने ७ जुलाई को आज़ाद मैदान से आंदोलन का

एलान किया था। लेकिन राज ठाकरे ने बाद में खुद एक ही मुद्दे पर दो अलग-अलग मोर्चे निकालने का कोई औचित्य नहीं है और मराठी जनता को एकजुट होकर संदेश देना चाहिए। इसके बाद संजय राऊत ने यह संदेश उद्धव तक पहुंचाया और दोनों पक्षों की सहमति से मोर्चे की तारीख ५ जुलाई तय की गई, क्योंकि ६ जुलाई को आषाढी एकादशी है और

मोर्चे के कारण श्रद्धालुओं को असुविधा हो सकती थी। राऊत ने स्पष्ट किया कि यह मोर्चा किसी राजनीतिक दल का नहीं होगा, बल्कि मराठी भाषी जनता की आवाज़ होगा। महाविकास आघाड़ी के सभी घटकों को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया जाएगा। मनसे की ओर से कांग्रेस को न्योता मनसे ने कट्टर विरोधी मानी जानेवाली कांग्रेस को भी इस आंदोलन में साथ

आने का न्योता दिया है। मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने कांग्रेस नेता विजय वडेहीवार से फोन पर बात कर उन्हें मोर्चे में शामिल होने का निमंत्रण दिया। वडेहीवार ने कहा कि वे इस पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर निर्णय लेंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने बयान दिया था कि यदि मराठी भाषा के लिए सभी दल एकजुट हो रहे हैं, तो कांग्रेस भी साथ होगी। देशपांडे और सरदेसाई की अगुवाई में तैयारियां शुरू राज और उद्धव ठाकरे के एकजुट होने के निर्णय के साथ ही दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में भी हलचल शुरू हो गई है। दादर में मनसे नेता संदीप देशपांडे और शिवसेना (उद्धव गुट) के विधायक वरुण सरदेसाई ने मुलाकात कर मोर्चे की तैयारियों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने एक होटल में बैठकर मोर्चे की रूपरेखा तैयार की।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

सर्वसाधारण नागरिकों को सुविधाएं देने में नगर परिषद तत्पर रहे-अमरसिंह पंडित

२ करोड़ रुपये के विकास कार्यों का हुआ शुभारंभ



रिपोर्ट: गेवराई प्रतिनिधि

नगर परिषद का कार्य आम जनता की सेवा करना है और उसका उद्देश्य यही है कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, साथ ही व्यापारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलें। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता और व्यापारी वर्ग की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। यह अपील पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित ने शुक्रवार को गेवराई नगर परिषद द्वारा आयोजित विकास कार्यों

के उद्घाटन समारोह में की।

इस अवसर पर नगर परिषद की ओर से कुल २ करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इसमें १.५० करोड़ रुपये की लागत से व्यापारी संकुल (मार्केट कॉम्प्लेक्स) के निर्माण और नया बस स्टैंड से चार्वाक होटल तक सीमेंट कांक्रिट नाली निर्माण का कार्य शामिल है। उद्घाटन जय भवानी श्रृंगार, फैक्ट्री के चेयरमैन अमरसिंह पंडित के शुभहस्ते व मान्यवरों की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम में भवानी बैंक के चेयरमैन बप्पासाहेब मोटे, पूर्व नगराध्यक्ष विनोद सौंदरमल, पूर्व उपनगराध्यक्ष शेख खाजाभाई, पूर्व नगरसेवक जालिंदर पिसाळ, राधेश्याम येवले, कृष्णा मुखे, मंजूर बागवान, विलास सुतार, आवेज शरीफ, सय्यद नजीब, उत्तमराव सोलाने, रिपब्लिकन पार्टी के तालुकाध्यक्ष किशोर कांडेकर, राष्टवादी कांग्रेस के शहराध्यक्ष दीपक आतकर, संजय पुरणपोळे, बंटी सौंदरमल, धंपाल भोले, एडवोकेट

योगेश पाटील, एडवोकेट गौतम कांडेकर, एडवोकेट मनोज हजारे, दत्ता दाभाडे, संतोष आंधळे, मानवाधिकार अभियान के कडूदास कांबळे, मोहसिन बागवान, सुभान शेख, सुभाष गुंजाळ, विलास ठाकुर, दत्ता लाड, संतोष सुतार, वसीम फारुकी, जे.के. बाबुभाई, अक्षय पवार, संदीप मडके, रजनी सुतार, बाबा शेख, राजाभाऊ जवंजाळ, कमलाकर हातागळे, दादासाहेब चौधरी, खालिद कुरैशी, सतीश दाभाडे, विलास निकम, सुनील सुतार, श्याम सुतार, नावीद मशायक, सादेक शेख, बालराजे सोनकांबळे, अंसारी समेत राष्टवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

आगे बोलते हुए अमरसिंह पंडित ने कहा कि गेवराई शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसे जोड़ने वाले सड़कों का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि शहर के हर कोने का संतुलित विकास होना चाहिए, तभी संपूर्ण प्रगति संभव है।

संविधान बदलकर मनुस्मृति लागू करना RSS-भाजपा का आज भी सक्रिय एजेंडा: हर्षवर्धन सपकाळ

हर जागरूक नागरिक को लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी समझनी चाहिए

मुंबई | २७ जून २०२५
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को भारत का संविधान शुरू से ही स्वीकार नहीं है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बदलकर उसकी जगह मनुस्मृति लागू करना उनका छिपा हुआ एजेंडा रहा है, जो अब कोई रहस्य नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हाल ही में RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले द्वारा संविधान की प्रस्तावना से पंथनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने की मांग ने इस एजेंडा को एक बार फिर उजागर कर दिया है।



हर्षवर्धन सपकाळ ने अपने बयान में कहा कि संघ परिवार का उद्देश्य शुरू से ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना रहा है, और भाजपा व संघ से जुड़े नेताओं के वक्तव्यों से यह बात बार-बार सामने आती रही है। उन्होंने याद दिलाया कि २०२४ के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के कई नेताओं ने खुलेआम कहा था कि अगर उन्हें ४०० सीटें मिलीं तो वे संविधान में संशोधन करेंगे। इसके अलावा ठड्ड प्रमुख मोहन भागवत भी यह कह चुके हैं कि संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व आर्थिक सलाहकार विवेक देबरांय भी संविधान में बदलाव की वकालत कर चुके हैं। सपकाळ के अनुसार ये सभी बयान किसी संयोग या व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि एक लंबे समय से चल रहे सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य संविधान को कमजोर

कर देश को एक विशेष विचारधारा के अधीन करना है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सात महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट कहा था कि पंथनिरपेक्षता और समाजवाद भारतीय संविधान की आत्मा हैं। इसके बावजूद संघ और भाजपा से जुड़े लोग बार-बार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिससे जनता के बीच भ्रम फैल रहा है और संविधान की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने की एक सोची-समझी रणनीति है।

हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि भाजपा और ठड्ड के एजेंडे में हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान जैसे नारे प्रमुखता से शामिल हैं, जो देश की बहुलतावादी संस्कृति और लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ठड्ड और भाजपा को न तो संविधान मंजूर है और न ही राष्ट्रीय ध्वज जैसे संवैधानिक प्रतीक, इसलिए वे बार-बार इनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने देश के नागरिकों से अपील की कि वे इन प्रयासों को पहचानें और इनके खिलाफ एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहें। सपकाळ ने कहा कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर जागरूक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और उन शक्तियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो देश को एक विशेष विचारधारा में ढालना चाहते हैं।

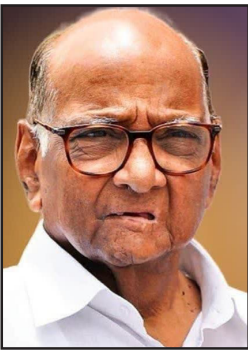
पहली से चौथी कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य बनाना उचित नहीं-शरद पवार

सरकार की नीतियों से खाड़ी देशों में भारत के खिलाफ फैल रही हैं गलतफहमियां

कोल्हापुर | २७ जून २०२५
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने आज कोल्हापुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहली से चौथी कक्षा तक हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाना एक गलत कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की ज़िद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों पर जबरन एक नई भाषा थोपना ठीक नहीं है। शरद पवार ने स्पष्ट किया कि भले ही

गंभीर अध्ययन होना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय मामलों पर ट्रंप पर साधा निशाना
अंतरराष्ट्रीय मामलों पर बात करते हुए शरद पवार ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ट्रंप अक्सर ऐसे निर्णय लेने का दावा करते हैं, जिनका अधिकार उनके पास नहीं होता। उन्होंने कहा कि ट्रंप किससे बात करते हैं, यह किसी को नहीं पता होता और उनके बयान कई बार बेचैनी पैदा करते हैं। यूरोप और पश्चिम एशिया में उनके व्यवहार के प्रति असंतोष पाया जाता है।

पवार ने कहा कि केवल ताकत के आधार पर छोटे देशों पर अपनी राय थोपना ठीक नहीं है। भारत को इस विषय में स्पष्ट और राष्ट्रीय हित आधारित रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि आज़ादी के बाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने अरब देशों की भावनाओं का सम्मान किया



है और हमेशा समर्थन दिया है। भारत ने भले ही इज़राइल के साथ कृषि संबंध बनाए हों, लेकिन राजनीतिक स्तर पर रिश्ते नहीं बढ़ाए थे ताकि अरब दुनिया से संबंध खराब न हों। सरकार की नीतियों पर गंभीर टिप्पणी

पवार ने मौजूदा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इनकी वजह से खाड़ी देशों में भारत के खिलाफ गलतफहमियां फैल रही हैं, जो देश के हित में नहीं हैं। पुणे का नाम बदलने पर भी जताई आपत्ति पुणे शहर के नाम बदलने को लेकर उठे विवाद पर शरद पवार ने कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल न दिया जाए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पुणे का नाम बाजीराव पेशवा के नाम पर ही क्यों रखा जाए? यदि बहादुरी ही पैमाना है तो और भी कई महान व्यक्तित्वों के नाम सामने लाए जा सकते हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान किसी से कम नहीं है, इसलिए इस तरह के मुद्दों के बहाने समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।

उमाकिरण प्रकरण में आज बीड़ शहर में शैक्षणिक बंद

स्वाभिमान संगठन का जोरदार प्रदर्शन, प्रा. सचिन उबाळे ने पीड़िता से सामने आने की अपील की



रिपोर्ट : बीड़ प्रतिनिधि

बीड़ शहर के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र माने जाने वाले उमाकिरण शैक्षणिक संकुल में कोचिंग क्लासेस के नाम पर छात्राओं के साथ कथित दुराचार का मामला सामने आने के बाद शुक्रवार, २८ जून को स्वाभिमान संगठन की ओर से संकुल के सामने तीव्र प्रदर्शन किया गया। संगठन के जिला अध्यक्ष प्रा. सचिन उबाळे ने घोषणा की कि इस प्रकरण के विरोध में आज बीड़ शहर में शैक्षणिक बंद का आयोजन किया गया है।

बताया गया है कि उमाकिरण परिसर में बड़ी संख्या में निजी कोचिंग क्लासेस चलते हैं, जहां बीड़ सहित अन्य जिलों से भी छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। इसी संकुल के एक क्लासेस में दो शिक्षकों पर एक छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत पर बीड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को कलंकित करनेवाली इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई है।

प्रदर्शन के दौरान स्वाभिमान संगठन के जिला अध्यक्ष प्रा. सचिन उबाळे ने कहा, पीड़िता को सामने आकर पूरी सच्चाई बतानी चाहिए, मैं तुम्हारा भाई बनकर हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। उन्होंने दोहराया कि इस गंभीर प्रकरण के विरोध में शहरभर में २८ जून को शैक्षणिक बंद रखा गया है। प्रदर्शन के माध्यम से संगठन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए शैक्षणिक परिसर में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

संजय राउत की मानहानि शिकायत पर मंत्री नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (उद्धव गुट) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा दायर मानहानि शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। संजय राउत ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नितेश राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें बदनाम करने वाले बयान दिए थे। मामले की सुनवाई के दौरान राणे अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके चलते मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ छद्म जारी किया। अदालत ने इस बात को गंभीरता से लिया कि बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद मंत्री नितेश राणे उपस्थित नहीं हुए। अब इस गैर-जमानती वारंट के बाद उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।



इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख जल्द तय की जाएगी, और राणे को अदालत के सामने पेश होना अनिवार्य होगा।

शिक्षण के पेशे को कलंकित करने वाले दरिंदों को बख्शा न जाए: राजेंद्र आमटे, सूरज चुगड़े

दरिंदों को नंगा कर के, गीले डंडे से चौराहे पर पीटो-नागरिकों की मांग

बीड़ (प्रतिनिधि):
बीड़ के प्रतिष्ठित उमाकिरण शैक्षणिक संकुल में प्रोफेशनल अकादमी के एक कोचिंग क्लास में छात्रा के साथ जो धिनौना कृत्य हुआ है, वह अत्यंत निंदनीय है। आज जब शिक्षक को राष्ट्रनिर्माण का प्रमुख स्तंभ माना जाता है, तब यदि वही शिक्षक व्यभिचारी और चरित्रहीन निकल जाए, तो छात्रों के लिए आदर्श कौन होगा? - यह सवाल उठाया है सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र आमटे और सूरज चुगड़े ने। उन्होंने कहा कि उमाकिरण संकुल में प्रोफेशनल कोचिंग क्लास के प्रशांत खाटोकर और प्रा. विजय पवार जैसे दरिंदों ने जो हरकत की है, वह पूरे शिक्षकीय पेशे को कलंकित करने वाली है। ऐसे दुष्कर्मी शिक्षकों पर सबसे कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। राजेंद्र आमटे और सूरज चुगड़े ने कहा कि भारत को आज विश्वगुरु के रूप में देखा जा रहा है और हमारी गुरु-शिष्य परंपरा अत्यंत गौरवशाली रही है। लेकिन बीड़ जैसी जगह पर शिक्षा की आड़ में ऐसा धिनौना व्यवहार हमारी इस परंपरा को शर्मसार करता है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपये खर्च कर माता-पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद से कोचिंग क्लास में भेजते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने और संस्कार देने के बजाय, ये दरिंदे ऐसे धिनौने काम करते हैं। उन्होंने मांग की कि ऐसे

आरोपियों को नग्न कर के गीले डंडों से चौराहे पर पीटा जाए और उन्हें किसी भी तरह से बचने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। राजेंद्र आमटे और सूरज चुगड़े ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करेंगे।

आरोपियों को नग्न कर के गीले डंडों से चौराहे पर पीटा जाए और उन्हें किसी भी तरह से बचने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। राजेंद्र आमटे और सूरज चुगड़े ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे आंदोलन करेंगे।